severely affecting public transport and agriculture;

(b) if so, whether Government has supplied the requisite quota of diesel to West Bengal in the months of January and February; and

(c) if not, what steps have been taken to supply the necessary quantity now?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) Due to the agitation in Assam and consequent closure of the three refineries located in that State and Barauni Refinery in Bihar, the availability of high speed diesel oil (HSD) in many of the States, including West Bengal, was affected. The State Government was advised to give highest priority to agriculture. Some effect may have been felt on public transport.

(b) The following are the details of sales of HSD for the months of January and February 1980 and the allocations for March, 1980 for West Bengal:—

Month	Quantity in metric tonnes
January /80 . .	50619 (approximately)
February /80- . .	50078 (approximately)
March /80 (allocations) .	61000 (approximately)

The State Government had been asking for additional allocations of HSD from time to time. It is not possible to indicate the percentage of demand that has been fulfilled.

(c) The allocation of HSD for March 1980 has already been increased substantially.

आलुओं को सुरक्षित रखने हेतु शीतागारों के लिए अतिरिक्त शीत संयंत्रों का लगाया जाना

781. श्री राम लाल राही :

क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिजली की कमी के कारण शीतागारों को दी जाने वाली बिजली में कटौती करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो आलुओं को सड़ने आदि से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) क्या इस विकट स्थिति पर काबू पाने के लिए शीतागारों में अतिरिक्त शीत संयंत्रों को लगाये जाने हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग). देश में कुछ राज्य बिजली की कमी अनुभव कर रहे हैं और यह स्थिति 1979 में मानसून के अभाव के कारण और भी गम्भीर हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप एक ओर तो जल विद्युत् केन्द्रों से बिजली की उपलब्धता में कमी हो गई है तथा दूसरी ओर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की मांग में वृद्धि हुई है । विद्युत विभाग ने कमी की अवधि में बिजली की आपूर्ति हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को कुछेक मार्गदर्शक सिद्धान्त परिचालित किए हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में अनिवार्य उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर बिजली की आपूर्ति करने और उसके पश्चात् उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों को वर्गीकृत प्राथमिकताओं की प्रणाली के अन्तर्गत बिजली की आपूर्ति करने की व्यवस्था है । कृषक उपभोक्ता तथा शीत भण्डारण संयंत्र अनिवार्य उपभोक्ताओं की पहली प्राथमिकता में शामिल है । तथापि, बिजली की कमी की वर्तमान स्थिति में अनेक बिजली बोर्ड अनिवार्य उपभोक्ताओं की भी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य नहीं हो पाए हैं। जहां तक शीत-भंडारों को बिजली की आपूर्ति करने का सम्बन्ध है विभिन्न राज्य सरकारों के बिजली बोर्डों से यह अनुरोध किया गया है कि वे चालू शीत भण्डारों को नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा उन्हें विशेष मामले के रूप में बिजली की कटौती से छूट दें । जल के प्राकृतिक वाष्पीकरण द्वारा ठण्डे किए जाने वाले प्रशीतन कक्षों का विकास करने हेतु प्रयोग भी किए जा रहे हैं ।

Purchase of Onions from Maharashtra by NAFED

782. SHRI UTTAMRAO PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the rate per quintal of onions which the NAFED has purchased from the Government of Maharashtra from July, 1979 to December, 1979.